

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

प्रश्न संख्या : 492

26 , 2019

प्रश्न संख्या

स्वास्थ्य परिचया सुविधाएं

\*492. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने नीति आयोग को एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें यह बताया गया है कि स्वास्थ्य परिचया सुविधाओं के मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्तर पर हैं; और
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा एनआरएचएम के अंतर्गत दूसरे राज्यों को तुलना में बिहार को बुनियादी स्वास्थ्य परिचया सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए और अधिक निधि आवंटित किए जाने को संभावना है ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर कम से कम प्राथमिक उपचार दिया जा सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (उत्तर प्रदेश)

(क) से (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(क): नीति आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामश से एक व्यापक राज्य स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट "स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत - राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रकों पर रिपोर्ट, जून, 2019" प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2015-16 (आधार वर्ष) से 2017-18 (संदर्भ वर्ष) की अवधि में उनके समग्र कार्य-निष्पादन और वृद्धिशील सुधार के आधार पर रक दी गई है। यह स्वास्थ्य सूचकांक तीन क्षेत्रों अर्थात् स्वास्थ्य परिणाम, गवर्नंस और सूचना तथा मुख्य इनपुट/प्रक्रियाओं में समूहबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के मुख्य पहलुओं को शामिल करने वाले 23 संकेतकों पर आधारित भारत में समग्र सूचकांक है। बेहतर तुलना के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तीन श्रेणियों अर्थात् बड़े राज्य (21), छोटे राज्य (8) और संघ राज्य क्षेत्र (7) में वर्गीकृत किया गया है।

राज्य स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए 21 बड़े राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश का समग्र स्वास्थ्य सूचकांक क्रमशः 32.11 और 28.61 है जो उन्हें सापेक्षिक रूप से निम्न स्थान पर ले जाता है। यह स्कोर उत्तर प्रदेश के 28.61 से लेकर केरल के स्कोर 74.01 तक अलग-अलग है।

(ख): चूंकि "सावजनिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल" राज्य का विषय है, इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। तथापि, राज्यों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनको स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित उच्च फोकस वाले राज्यों को गैर-उच्च फोकस वाले राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति उच्चतर संसाधन आवंटित किए जाते हैं।

\*\*\*\*\*